

वर्ष 2030 तक एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत

प्रलिस के लयः

सकल घरेलू उत्पाद (GDP), स्टार्टअप, प्रत्यक्ष वदेशी नवऱश (FDI), 'मेक इन इंडया', इलेक्ट्रॉनक्स पर राषट्रीय नीतऱ-2019 (NPE 2019)

मेन्स के लयः

भारत की अर्थव्यवस्था की स्थतऱऱ से संबंघतऱ चतऱएँ और इस संबंघ में उठाए गए कदम

चरचा में क्यौं?

'इंफॉर्मेशन हैंडलंग सर्वसऱऱ' (IHS) मारकटऱ रऱपोर्ट के मुताबकऱ, भारत वर्ष 2030 तक जापान को एशया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में पीछे छोड़ सकता है ।

- भारत वर्तमान में अमेरका, चीन, जापान, जर्मनी और यूनाइटेड कंगडम के बाद छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ।
- आईएचएस मारकटऱ दुनया भर में अर्थव्यवस्थाओं को संचालतऱ करने वाले प्रमुख उद्योगों और बाज़ारों के लयऱ सूचना, वऱश्लेषण और समाधान प्रस्तुत करने वाली एक अग्रणी वैश्वकऱ कंपनी है ।

नोटः कसऱी देश की समग्र अर्थव्यवस्था का आकार प्रायः उसके सकल घरेलू उत्पाद द्वारा मापा जाता है, जो कसऱी दयऱ गए वर्ष में कसऱी देश के भीतर उत्पादतऱ सभी अंतमऱ वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है ।

प्रमुख बढऱ

- **जीडीपी अनुमानः**
 - मूल्य के संदरभ में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार वर्ष 2021 में 2.7 टरलऱयऱन अमेरकऱी डॉलर था, जसऱके वर्ष 2030 तक बढकर 8.4 टरलऱयऱन अमेरकऱी डॉलर हो जाने का अनुमान है ।
 - यह बढतेरी अर्थव्यवस्था के मामले में जापान को पीछे करने हेतु काफी है, जसऱसे भारत वर्ष 2030 तक एशया-प्रशांत कषेत्तर में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा ।
 - पछऱले वतऱतऱ वर्ष में 7.3% की गरऱवट की तुलना में वर्ष 2021-22 में भारत की वकऱस दर 8.2% रहने का अनुमान है ।
 - हालाँकऱ चालू वतऱतऱ वर्ष (FY) की गतऱवर्ष 2022-23 में भी जारी रहेगी और भारत 6.7% की वृद्धऱ दर हासलऱ करेगा ।
- **वभिन्न कषेत्तरों की भूमकऱऱः**
 - भारत की वकऱस दर को बढाने में ई-कॉमर्स कषेत्तर के साथ-साथ वनऱरऱमाण, बुनयादी ढाँचा और सेवा कषेत्तर की बड़ी भूमकऱऱ है ।
 - इतना ही नही, डजऱटऱलीकरण बढने से आने वाले समय में ई-कॉमर्स बाज़ार और बड़ा हो जाएगा ।
 - एक रऱपोर्ट के मुताबकऱ वर्ष 2030 तक 1.1 अरब भारतीयों के पास इंटरनेट होगा, वर्ष 2020 में यह संख्या 50 करोड़ थी ।
- **वृद्धऱ दरः**
 - कुल मलऱकर भारतीय अर्थव्यवस्था का भवऱष्य मज़बूत और स्थऱरऱ दखऱता है, जो इसे अगले दशक में सबसे तेज़ी से बढने वाला देश बनाता है ।
 - लंबी अवधऱ में भी बुनयादी ढाँचा कषेत्तर और स्टार्टअप जैसे तकनीकी वकऱस भारत की तीव्र वकऱस दर को बनाए रखने में बड़ी भूमकऱऱ नभाएंगे ।
 - दुनया की सबसे तेज़ी से बढती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के नाते भारत उद्योगों की एक वसऱतृत शृंखला में बहुराषट्रीय कंपनऱयों के लयऱ सबसे महत्त्वपूर्ण दीर्घकालकऱ वकऱस बाज़ारों में से एक बन जाएगा, जसऱमें ऑटो, इलेक्ट्रॉनक्स, परसऱपत्तऱ प्रबंधन, सवास्थय देखभाल और सूचना प्रौद्योगकऱी एवं रसायन जैसे वनऱरऱमाण उद्योग तथा बैंकगऱ, बीमा जैसे सेवा उद्योग शामिल हैं ।

- **मध्यम वर्ग का समर्थन:**
 - भारत को सबसे ज्यादा मदद उसके विशाल मध्यम वर्ग से मिलती है, जो उसकी मुख्य उपभोक्ता शक्ति है।
 - अगले दशक में भारतीय उपभोक्ता खर्च भी दोगुना हो जाएगा। यह वर्ष 2020 में 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2030 में 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो सकता है।
- **एफडीआई अंतरवाह:**
 - पछिले पाँच वर्षों में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह में बड़ी वृद्धि 2020 और 2021 में भी मजबूत गतिके साथ जारी है।
 - इसे वैश्विक प्रौद्योगिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) जैसे कि Google और Facebook से निवेश के बड़े प्रवाह से बढ़ावा मिला रहा है, जो भारत के बड़े घरेलू उपभोक्ता बाजार की ओर आकर्षित हैं।
- **भारत की अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति:**
 - वर्ष 2021-22 की पहली त्रिमाही के सकल घरेलू उत्पाद के अनंतिम अनुमानों के अनुसार, मौजूदा कीमतों पर भारत की GDP वृद्धि वर्ष 2012 की पहली त्रिमाही में 694.93 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी।
 - भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा **यूनिफॉर्म बेस** है, जहाँ 21 से अधिक यूनिफॉर्म का सामूहिक मूल्य 73.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।

अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये सरकार की पहल

- **'मेक इन इंडिया' और इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 पर राष्ट्रीय नीति (एनपीई 2019)**
- **वभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई)**
- **प्रमुख दूरसंचार क्षेत्र के सुधार:**
 - सितंबर 2021 में प्रमुख दूरसंचार क्षेत्र में सुधारों को मंजूरी दी गई है, जिससे रोजगार, विकास, प्रतस्पर्द्धा और उपभोक्ता हितों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
 - समायोजित सकल राजस्व और बैंक गारंटी (BGs) का युक्तिकरण तथा स्पेक्ट्रम साझाकरण को प्रोत्साहित करना प्रमुख सुधारों में से है।
- **डीप ओशन मशिन:**
 - भारत सरकार ने अगस्त 2021 में अगले पाँच वर्षों में 4,077 करोड़ (553.82 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के बजट परियोजना के **साथ डीप ओशन मशिन (DOM)** को मंजूरी दी।
- **अक्षय स्रोतों पर ध्यान देना:**
 - ऊर्जा उत्पादन करने के लिये भारत अक्षय स्रोतों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह वर्ष 2030 तक अपनी ऊर्जा का 40% गैर-जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने की योजना बना रहा है, जो वर्तमान में 30% से अधिक है और वर्ष 2022 तक अपनी **निवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 175 गीगाटन (GW)** तक बढ़ाना है।
 - इसके अनुरूप भारत और यूनाइटेड किंगडम ने संयुक्त रूप से मई 2021 में वर्ष 2030 तक जलवायु परिवर्तन में सहयोग एवं मुकाबला करने हेतु एक 'रोडमैप 2030' लॉन्च किया।

आगे की राह

- एक ओर जहाँ वर्ष 2021 में वननिर्माण और निर्माण जैसे क्षेत्रों में तेजी से सुधार हुआ, वहीं दूसरी ओर, कम-कुशल व्यक्ति, महिलाएँ, स्वरोजगार वाले लोग और छोटी फर्मों पीछे रह गईं।
- बुनियादी ढाँचा और वननिर्माण दो स्तंभ हैं जिनका उपयोग संरचनात्मक रूप से विकास को आगे बढ़ाने के लिये किया जाना चाहिये।
 - हालाँकि बुनियादी ढाँचे के निर्माण या निवेश चक्र के पुनरुद्धार के लिये, सामान्य तौर पर नज्दी क्षेत्र को भी योगदान देना शुरू करना होगा।
 - नज्दी कॉरपोरेट और घरों में पुनरुद्धार के लिये बुनियादी बातें वित्तीय संस्थानों, विशेष रूप से बैंकों के साथ बेहतर स्थिति, कॉरपोरेट्स और कम ब्याज दर शासन के साथ उभर रही हैं।
- वृत्ति वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था की रकवरी पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि घरेलू आय कतिनी तेजी से बढ़ रही है एवं अनौपचारिक क्षेत्र और छोटी फर्मों में गतिविधि सामान्य रहती है।
- नज्दी क्षेत्र को लैबी अवधि के लिये संपत्ति निर्माता करने के साथ भारत में व्यापार को आसान बनाने तथा लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना चाहिये।
- कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी भारत के विकास का एक प्रमुख चालक है। इसलिये भारत को महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी चाहिये।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस